Fourth Series Vol. XII - No. 1

Monday, February 12, 1968
Magha 23, 1889 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Fourth Session)

(Vol. XII contains Nos. 1-10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : *Rs. 1.00*

CONTENTS

[*Fourth Series, Vol. XII—February* 12, 1968/*Magha* 23, 1889 (*Saka*)]

No. 1—*Monday, February* 12, 1968/*Magha* 23, 1889 (*Saka*)

	COLUMNS
Alphabetical list of Members	(i)
Officers of the Lok Sabha	(ix)
Government of India—Ministers, Ministers of State, etc.	(xi)
Member sworn (Shri S. M. Krishna)	1
President's Address—Laid on the Table	1—33
Obituary references	33
Shrimati Indira Gandhi	35—36
Shri Ranga	36—37
Shri Atal Bihari Vajpayee	38—39
Shri Anbazhagan	40
Shri H. N. Mukerjee	40—42
Shri S. M. Joshi	43—45
Shri P. Ramamurti	45—46
Shri Nath Pai	46—48
Shri N. C. Chatterjee	48—49
Shri Prakash Vir Shastri	50—51
Shri Deorao Patil	51
Shrimati Nirlep Kaur	51—53
Shri J. B. Kripalani	53—54

3067(ai)LSD—1.

LOK SABHA

Monday, February 12, 1968/Magha 23, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Forty Minutes past Twelve of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

(*Shri S. M. Krishna*)

MR. SPEAKER: Secretary may call out the name of the Member who has come to take oath

SECRETARY: Shri S. M. Krishna from Mandya constituency.

SHRI K. LAKKAPPA: (Tumkur): Now I demand the resignation of Shri Nijalingapa.

SHRI NATH PAI (Rajapur): It is a unanimous demand. Nobody said 'No' even.

Shri S. M. Krishna (Mandya-Mysore).

12.41 hrs.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY: Sir, I lay on the Table a copy of the. President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 12th February, 1968.

Presidents' Address

संसद् सदस्यगण,

नये वर्ष के इस प्रथम अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है ।

पिछला साल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। लगातार दूसरे साल भी देश ने अभूतपूर्व सूखे और अभाव का सामना किया। पहले के अकालों के विध्वंस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा गौरव है कि समूचे राष्ट्र ने एक जुट होकर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर आये भयंकर खतरे का सामना कर सफलता प्राप्त की। इस सफलता के कई विशेष कारण हैं : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समयोजित और महत्वपूर्ण कार्य, ऐच्छिक संस्थाओं की निष्ठापूर्ण सेवा, मित्र राष्ट्रों की सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की कुशलता और उनके कठिन परिश्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अटूट हिम्मत और साहस का बल।

एक साल पहले भविष्य अन्धकारपूर्ण दीखता था लेकिन निराशा के बादल अब हटने लगे हैं। इस साल अनाज की पैदावार पिछले सभी सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। आमतौर पर यह अन्दाज लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग साढ़े नौ करोड़ टन अनाज पैदा होगा जो 1966–67 की तुलना में दो करोड़ टन ज्यादा और 1964–65 से, जब कि बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ था 60 लाख टन ज्यादा होगा। पैदावार की इस वृद्धि से खाद्य स्थिति में सुधार की आशा है। फिर भी इस साल जो उपज होगी उसका बहुत अधिक हिस्सा तो सरकारी और निजी खाली गोदामों को भरने में चला जाएगा। खाद्य स्थिति में स्थिरता लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि काफी बड़ा बफर स्टाक तैयार किया जाए। इस के लिए यह भी जरूरी है कि

नियंत्रित दाम पर सरकार की ओर से अनाज का बटवारा जारी रखा जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सरकार अपने देश में अन्न संग्रह के लिए बराबर कोशिश कर रही है और प्रयास है कि 30 लाख टन का एक बफर स्टाक तैयार किया जाय। इन सब के लिए देश में पैदावार को बहुत अधिक गतिशील बनाने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद बाहर से कुछ आयात करना जरूरी होगा।

यह सही है कि अच्छे मौसम की वजह से पैदावार बढ़ी है लेकिन इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कृषि की पैदावार में जो सफलता हमें मिली है उसमें खेती के नए तरीकों का बहुत बड़ा योगदान है। 1966–67 में 50 लाख एकड़ भूमि पर अधिक उपज देने वाले बीज बोये गये थे। पिछली खरीफ की फसल में 60 लाख एकड़ भूमि पर यह बीज बोया गया था और अनुमान है कि मौजूदा रबी की फसल में 90 लाख एकड़ भूमि में यह बीज बोया गया है। कपास, जूट, ईख, तम्बाकू, मूंगफली जैसी व्यापारिक फसलों की पैदावार भी बढ़ने की आशा है। 30 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि पर लघु सिंचाई कार्यक्रम लागू होगा। नाईट्रोजन पूरक खाद का उपयोगअ भी दहुत अधिक बढ़ा है। और 1965–66 की तुलना में इसकी खपत इस साल लगभग दूनी हो गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 3 चौथाई अधिक इलाके में पौधासंरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ट्रैक्टर, बिजली से चलने वाले खेती के उपकरण, पम्प, डीजल इंजन और खेती के दूसरे औजार बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। खेती के लिए उधार पर रुपये देने की व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। खेती संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण, खोज और विस्तार के कार्यक्रम को अमल में लाने के बारे में भी लगातार तरक्की हो रही है। खेती के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कम से कम समय में अपने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।

खेतों में पैदावार बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1966–67 में जो हमारी आय थी उसमें 10.8 प्रतिशत वृद्धि की इस साल आशा है। खेती की पैदावार बढ़ाने की वजह से दामों का ऊपर बढ़ना भी कुछ कम हुआ है। 1966 में थोक कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गयी थीं। किन्तु मौजूदा साल में इनकी वृद्धि 5.7 प्रतिशत हुई है। मूल्यों में स्थिरता आने के अच्छे आसार दिखाई पड़ रहे हैं फिर भी जैसा कि मैंने आप से कहा, मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी होगा कि अनाज के सरकारी वितरण की व्यवस्था कायम रहे और राजकोष, आर्थिक तथा आय संबंधी नीति पर हमारा अनुशासन बना रहे।

पिछले दो सालों में जो भयंकर सूखा पड़ा उस का असर कारखानों की पैदावार पर भी हुआ। कारखाने जो खेत की पैदावारों पर मुनहसिर थे उन को कच्चा माल पूरा नहीं मिल सका और आमदनी में कमी होने के कारण मांग भी कुछ गिर गई। कुछ पूंजी और उत्पादक माल बनाने वाले कारखानों के सामने भी कम मांग की समस्या आई चूंकि पूंजी लगाने की शक्ति में कमी हो गई थी। औद्योगिक विस्तार की गति धीमी होने की वजह से रोजगार हासिल करने में खासकर हुनरमन्द लोगों को दिक्कत हुई। सरकार ने बाहर भेजने और देश में खपत के लिये कुछ चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास कदम उठाये हैं, इन में कर्ज की शर्तों में ढ़ील देना, सरकारी कारखानों द्वारा अग्रिम आर्डर देना और जो चीज देश में बनाई जाती हैं उन को विदेशों से नहीं मंगाने की नीति शामिल है। खेती की पैदावार बढ़ाने से राष्ट्रीय

आय में जो वृद्धि हुई है उस से यह आशा की जाती है कि अगले साल औद्योगिक उत्पादन की बहुत सी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी ।

पिछले दो सालों में लागत और मूल्य के बराबर बढ़ते रहने तथा खेती की पैदावार में बहुत कमी होने के कारण हमारे निर्यात को धक्का पहुंचा । लेकिन अभी अन्न की अच्छी उपज तथा कारखानों के लिये खेती से अधिक कच्चे माल प्राप्त होने के कारण अगले साल हमारे निर्यात के बढ़ने की आशा है । मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में 1966–67 के इन सात महीनों की तुलना में हमारा निर्यात 5.7 प्रतिशत अधिक रहा है । इंजीनियरी के सामान बनाने वाले कारखानों के पास निर्यात के लिए काफी आर्डर मिल चुके हैं औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से यह आशा की जाती है कि विदेशों के बाजारों के लिए हम अधिक चीजें बनाने में समर्थ हो सकेंगे ।

तरह तरह के सामान बनाने और उत्पादन में वृद्धि, माल बेचने की कला के विकास और क्षमता बढ़ाने के लिये उत्पादकों और निर्माताओं को सरकार बराबर सहायता देती रही है । अपने देश के उत्पादन के निर्यात को बढ़ाने और विदेशों में हमारे माल की ज्यादा मांग बढ़ाने की कोशिश हुई है । विदेश स्थित हमारे मिशनों से इसके लिये बराबर रोजबरोज सम्पर्क रखा जा रहा है और द्विदेशीय करार तथा बहु-पक्षीय वार्ता भी हुई है ? समाजवादी देशों के साथ जो हमारे करार हुए हैं उनसे हमारे व्यापार का बराबर विस्तार होता रहेगा । कैनेडी द्वारा प्रारंभ करारों के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर हमारे निर्यात-कर्ताओं को माल भेजने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे । संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के साथ जो हमारा त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग करार हुआ है उससे पारस्परिक व्यापार बढ़ेगा और दूसरे विकासशील देशों के साथ हमारे व्यापारिक सहयोग के विस्तार का आधार प्राप्त होगा । निर्यात का विस्तार हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है और उसे सदा बढ़ावा दिया जाएगा ।

निर्यात से अधिक आयात तथा विदेशी ऋण को चुकाने के भार, अनाज के आयात और निर्यात के लिये जो चीजें तैयार की जाती हैं उन के लिये विदेशी माल को मंगाने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पिछले साल कठिन रही । विदेशी ऋण पर खर्च की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में सरकार ने मित्र देशों तथा अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मांगी है । इस ओर हमें कुछ हद तक सहायता प्राप्त भी हुई और चर्चा आगे चल रही है । विदेशी मुद्रा की जो राशि अपने पास थी उसमें कमी हुई इसलिए यह जरूरी हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ और अल्पकालीन सहायता ली जाए ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक सफलता-पूर्वक चलाने की किसी भी योजना के लिए अपने व्यापारिक जहाजों का विकास और बंदर-गाहों की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं—तूतीकोरिन और मंगलौर बंदरगाहों का विकास और हल्दिया गोदी का निर्माण, बंदरगाहों पर जो सुविधाएं हैं उन का विस्तार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पुनर्गठन और आधुनिक बनाया जाना । कोचीन में सरकारी क्षेत्र द्वारा दूसरे शिपयार्ड की स्थापना की गई है जहां 66,000 डेडवेट टन जहाजों का निर्माण हो सके और 85,000 डेडवेट टन तक के जहाजों को मरम्मत की सुविधा हो । जहां तक हमारे व्यापारिक जहाजों की भारवहन क्षमता का प्रश्न है वह लगभग 20 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गयी है । सरकार ने एक ऐसे आयोग की भी स्थापना की है जो बड़े बड़े बन्दरगाहों की आर्थिक समस्याओं पर विचार करे और उनके आधुनिक बनाये जाने के संबंध में सुझाव दे ।

परिवार नियोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा किए बगैर वार्षिक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा । इस वर्ष इस कार्यक्रम में जोरदार प्रगति हुई । देहाती और शहरी आबादी में बहुत से नए वर्गों के लोगों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया । अनुमान है कि 28.50 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं । अब तक किसी एक वर्ष की जो संख्या रही है, उससे यह संख्या कहीं ज्यादा है । फिर भी, वार्षिक जन्म दर को एक हजार में लगभग 40 से 25 तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इससे भी ज्यादा और लगातार कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह इरादा किया गया है कि अगले वर्ष 60 लाख अतिरिक्त स्त्री–पुरुषों को परिवार नियोजन के तरीकों और सेवाओं की परिधि में ले आया जाए। आबादी को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है ।

भविष्य की ओर देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा काम अर्थ-व्यवस्था को नए सिरे से गतिशील बनाना है । पिछले दो वर्षों में इसे जो जबर्दस्त धक्के लगे हैं, उन्हें पार कर यह अब संभल रही है । सरकार का ख्याल है कि योजना के तरीके से ही कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में देश आगे जा सकता है ।

योजना कमीशन चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है; यह योजना अब अप्रैल 1969 से चालू होगी । इस बीच विकास संबंधी आयोजन वार्षिक योजनाओं के आधार पर होता रहा है । 1968–69 वार्षिक योजना जल्दी ही आपके सामने रखी जाएगी । सरकार और योजना कमीशन दोनों ही स्वभाविक रूप से इसके लिये उत्सुक हैं कि योजना समय पर तैयार हो जाए ताकि 1968–69 के बजट में उसे शामिल किया जा सके ।

हमें अपनी योजनाओं को तैयार करने के लिए कई सवालों पर ध्यान देना है । इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं : संसाधनों को इकट्ठा करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग-धंधों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना और विज्ञान तथा टैक्नोलोजी का समुचित उपयोग करना । सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में काफी हद तक बचत किए बगैर आंतरिक संसाधनों को अच्छी तरह इकट्ठा नहीं किया जा सकता । लेकिन ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्म संयम से काम लें और कम खर्च कर बचत करें क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते । कारगर ढंग से संसाधन इकट्ठे किए जा सकें, इसके लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है जैसे कि टैक्स के कानून सरल कर दिए जाएं, टैक्स की प्रक्रिया में सुधार किया जाए और समाहरण तंत्र को समुन्नत किया जाए ।

सरकारी क्षेत्र की क्षमता को फौरन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है । विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं ने जो सलाह दी है, उसके संदर्भ में सरकार इस क्षेत्र के गठन और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर रही है । अच्छा प्रबन्ध, कर्मचारियों के संबंध में अधिक युक्तियुक्त और सूविचारित नीति, श्रमिकों के साथ सुधरे हुए संबंध और वरीयताओं (प्रायोरिटीज) तथा मूल्यांकनों को दृढ़ता से लागू करके प्रभावशाली तरीके से किफ़ायत करने के संबंध में खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है ।

सदस्यों को याद होगा कि संसद के पिछले अधिवेशन में उप-प्रधान मंत्री ने आम बीमा को सामाजिक नियंत्रण में लाने के बारे में सरकार के निर्णय पर एक बयान दिया था ।

सरकार का इरादा है कि उस बयान में जो निर्णय बताए गए थे, उनपर अमल करने के लिए चालू सत्र में एक बिल पेश किया जाए ।

हमारे आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और (टैक्नोलोजी) का प्रयोग करने को सरकार जो महत्व देती है, उसका मैंने जिक्र किया । इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति यह है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में, सरकारी मशीनरी और उद्योग में उत्पादक तथा रचनात्मक तालमेल हो ।

समीक्षाधीन वर्ष में थुम्बा इक्वाटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन औपचारिक रूप से समर्पित किया गया । केन्द्र से जो पहला रोहिणी राकेट तैयार किया गया था, उसे थुम्बा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया अहमदाबाद में एक्सपेरीमेंटल सैटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन पूरा कर लिया गया है और अरवी में एक नया स्टेशन तैयार किया जाएगा । यह आशा की जाती है कि एटमी शक्ति के क्षेत्र में तारापुर का एटामिक पावर प्रोजेक्ट इस वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा । दो और एटामिक पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं ।

सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हमारा प्रशासनिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह न सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करे बल्कि लोगों का विश्वास भी प्राप्त करे । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की गई थी । उसने कई रिपोर्टें दी हैं जिनमें व्यापक रूप से लोगों ने दिलचस्पी ली है । हमारे देश में इस तरह की व्यापक जांच पहली बार की गई है । इस आयोग के सामने नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्या थी और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं । सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक ऐसे सांविधिक तंत्र की स्थापना की जाए जो कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय की कथित शिकायतों की जांच करे । इस तंत्र का अध्यक्ष होगा एक लोकपाल, जिसे केंद्रीय मंत्रियों से और सचिवों के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होने वाले आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा । यह लोकपाल लोकायुक्त के दर्जे के दो अन्य प्राधिकारियों के कार्य संचालन में भी तालमेल रखेगा । पहला तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सचिवों के दर्जे से कम दर्जे के केन्द्रीय सरकारी नौकरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा । संसद के वर्तमान सत्र में इस आशय का एक बिल पेश किया जाएगा ।

हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ खास पहलुओं पर सरकार को निरंतर चिंता बनी रहती है । बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय है जिससे परेशानी होती है और खास तौर से पढ़े लिखे और तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से योग्य नौजवानों की । फिर भी हमें यह समझना है कि इसके कोई सरल और अल्प-कालिक समाधान नहीं है । हमारी आर्थिक उन्नति से रोजगार के जो संवर्द्धित अवसर प्राप्त होंगे, उनसे ही ये समस्याएं हल की जा सकती है क्योंकि ऐसा करने से शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों से निकले हुए लोगों को खपाया जा सकेगा । इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा । भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में योजना कमीशन समीक्षात्मक पुनरीक्षण कर रहा है । इस बीच सरकार को यह पूरी आशा है कि हमारे नव युवा स्त्री और पुरुष, जो श्रम की गरिमा को पहचानते हैं, इस तरह के रोजगार के अवसरों को स्वीकार करने में नहीं हिच-

किचाएंगे जो अब सुलभ हैं चाहेवे कार्य उनकी तकनीकी योग्यता के समकक्ष न बैठते हों।

हमारे समाज के अब तक के अविकसित वर्गों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, और पिछड़ी जातियों—की सामाजिक–आर्थिक उन्नति सरकार के लिए अत्यंत रुचि और चिंता का विषय रहा है। हालांकि उनकी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो भी सरकार यह जानती है कि बहुत कुछ करना बाकी है। इस लिहाज से भी, हमारी इस समस्या का आखिरी उत्तर हमारी अर्थ–व्यवस्था के जल्दी समुन्नत होने में ही निहित है।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दृष्टियों से आर्थिक उन्नति और बढ़ोतरी के विषय में हमारी सारी आशाएं इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करें, हमारे देशवासी परिश्रम करें, उनमें आत्मानुशासन की भावना जागे, उनके श्रम से उत्पादन बढ़े और उद्योग-धंधों में शांति बनी रहे।

यह चिंता का विषय है कि विभाजक शक्तियां सिर उठाती रही हैं जिसके कारण क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर झगड़े और फिसाद हुए हैं। यह मामला राष्ट्र के लिए गहरी चिंता का विषय है जो दलगत संबंधों से ऊपर है। यह मानकर ही संसद के दोनों सदनों ने सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयत्नों का स्पष्ट समर्थन किया था। देश के विभिन्न भागों में हुई बड़ी–बड़ी घटनाओं की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व–न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमीशन की नियुक्ति से सरकार के इस दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है कि वह अपनी भरपूर कोशिश से विध्वंसकारी शक्तियों को मिटाने के लिये तत्पर है।

यह स्वाभाविक है कि हमारे जैसे बड़े देश में कुछ-न कुछ समस्यायें यहां-वहां लोगों को आंदोलित करती रहें फिर भी, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसमें ये सारी समस्याएं लोगों के प्रतिनिधियों के समक्ष लाई जा सकती हैं और उनपर निष्पक्षता से विचार किया जा सकता है। तर्कसंगत और समझा-बुझा कर विवाद तय करना ही लोकतंत्रीय ढंग है। गली–मोहल्लों में हिंसात्मक उपद्रव लोकतंत्रात्मक पद्धति की नींव को कमजोर बनाते हैं।

सरकार के लिये यह बड़े ही खेद का विषय है कि देश के कुछ भागों में भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदर्शन हों और कानून भंग किये जाएं। सरकार की भाषागत नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में एकता सुदृढ़ हो और लोगों में एकता बढ़े और इसके साथ ही समुदाय के तमाम वर्गों को आत्माभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। सरकार को पूरी आशा है कि भाषा के बारे में तमाम विवाद अब समाप्त कर दिये जाएं। हमारी भाषा नीति और कार्यक्रमों पर अमल करने से जो व्यवहारिक समस्याएं उठ खड़ी हों, उनपर समझ-बूझ और आपसी समझौते की भावना से विचार किये जाएं।

सरकार इस बात से आश्वस्त है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समझ-बूझ से राष्ट्रीय हित का साधन निरंतर होता रहेगा। वह अपनी ओर से इसकी पुनः पुष्टि करती है कि वह दलगत संबंधों की परवाह किए बगैर राज्य सरकारों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहती है। और इसके बदले में वह राज्य सरकारों से समान सहयोग की अपेक्षा करती है।

संसद् में विभिन्न राजनीतिक दलों के के नेताओं के साथ और असम के विभिन्न मतदलों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा करके असम के पुनर्गठन के प्रश्न पर आम राय स्थिर करने के लिये सरकार ने बराबर कोशिश की है। उम्मीद की जाती है कि उनके सहयोग से निकट भविष्य में कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, स्वर्गीय मेहरचन्द महाजन ने मैसूर और महाराष्ट्र तथा मैसूर और केरल के बीच सीमा के समजन संबंधी मसले पर अपनी रिपोर्ट पिछले अगस्त में पेश कर दी थी। सरकार का विश्वास है कि ये सीमा समस्याएं संतोषजनक ढंग से सुलझ जाएंगी।

हमारी सीमाओं पर बराबर जो खतरा बना हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी रक्षा सेनाओं को लगातार अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं; उन्हें साज सामान से फिर से लैस करने और उनका आधुनिकीकरण करने का काम बराबर चल रहा है। सुलभ साधनों के अनुसार, समग्र रक्षा योजना के ही अंग के रूप में अपने वायु रक्षा के प्रबंध भी बेहतर किये गए हैं। नौसेना के आधुनिकीकरण करने और जहाजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी हमने संतोषजनक प्रगति की है। रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती रहेगी।

सीमाओं पर दो पड़ोसियों से खतरा अब भी बना हुआ है। हम उन के साथ मित्रतापूर्ण और शान्तिपूर्ण संबंध कायम करना चाहते हैं लेकिन अपने देश की प्रादेशिक एकता की रक्षा के लिए हम जरूरी त्याग करने के लिये तैयार हैं।

शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और सहयोग के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना अब भी हमारी विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। हमारे ये उद्देश्य राष्ट्रीय हित से मेल खाते हैं। सरकार का यह विश्वास है कि आज की दुनिया में सिर्फ सह-अस्तित्व का सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है।

आज दुनिया में संघर्ष और तनाव के अनेक स्त्रोत हैं। इन में सबसे खतरनाक वियतनाम और पश्चिम एशिया के संघर्ष हैं। सरकार का विश्वास है कि वियतनाम का दुखद संघर्ष सिर्फ राजनीतिक तरीकों से ही हल किया जा सकता है, संगीन की नोक पर नहीं। इसलिए, सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सबसे पहिले उत्तर वियतनाम पर बमबारी बिना शर्त बंद की जानी चाहिए। संसार के अधिकाधिक देशों की अब यही धारणा बनती जा रही है।

पश्चिम एशिया का संकट अभी तक टला नहीं है। समुचित समाधान में जितनी देर लगेगी उतनी ही यह समस्या ज्यादा पेचीदा बनती जाएगी। सुरक्षा परिषद् के एक सदस्य के रूप में हमने उन सभी प्रयत्नों का निरंतर समर्थन किया है जो इस समस्या का शीघ्र और न्यायोचित समाधान ढूंढने के लिए किए गए हैं ताकि किसी राज्य को आक्रमण से हुए लाभों को अपने पास रखने की इजाजत न दी जा सके और इस क्षेत्र का हर एक राज्य अपने पड़ौसियों के साथ शांतिपूर्वक सुरक्षित रह सके।

हमें इस बात की खुशी है कि बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और उनके साथ आपसी सद्भावना और सहयोग के संबंध धीरे-धीरे बराबर बढ़ रहे हैं। इन देशों के विशिष्ट नेताओं की भारत यात्रा में और प्रधान मंत्री की तथा उनके कुछ दूसरे साथियों की इन देशों की यात्राओं में यह बढ़ता हुआ सौहार्दभाव प्रतिबिम्बित हुआ है।

यह बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध अब भी असंतोषजनक बने हुए हैं। हमने सोचा था कि सत्यनिष्ठ ताशकंद घोषणा से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग के संबंध विकसित करने का आधार मिल जायेगा। सरकार ने अनेक प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े दो पड़ौसी देशों के अनुरूप संबंधों को सामान्य करने की सच्चे हृदय से कोशिश की है। आपसी संपर्कों को फिर से जोड़ने, टूटे हुए संचार सूत्रों को पूरी तरह फिर से स्थापित करने और व्यापार तथा वाणिज्य को फिर से चालू करने से दूसरे मसलों पर विचार करने में सहूलियत होगी। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि बुद्धिमानी और राजनीतिज्ञता से काम लिया जाएगा जिससे कि दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों के फायदे के लिये और इस क्षेत्र की शांति और समरसता के हित में मित्रता और समझ-बूझ का ताना बाना धीरे धीरे तैयार हो जाए।

जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है हमेशा हमने उनका भला चाहा है, हमारे लिये चीन से इतनी उम्मीद रखना बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों पर अपनी मर्जी के अनुसार चलने के हमारे अधिकार का वह सम्मान करेगा। परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का स्थायी आधार मिल सकता है। हम इन सिद्धांतों पर चीन के साथ हअपने संबंध स्थापित करने को हमेशा तैयार हैं।

हमारे देश के लोगों को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाने के आन्दोलन में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त है। हमने जातीय भेदभाव और दमन की चिनौनी प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया है। हम दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाली उपनिवेशों के दमित लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति दिलाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। जो लोग रंगभेद की बर्बर नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन बराबर मिलता रहेगा।

अफ्रीका के स्वतंत्र और प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों के साथ हमारे संबंध बहुपक्षीय हो गए हैं। इनमें से कई देशों के साथ हम आर्थिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

यह बड़े संतोष की बात है कि यूरोप में तनाव कम करने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ खुद हमारे संबंध संतोषजनक रूप से बढ़ रहे हैं चाहे इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धान्त कैसे भी क्यों न हों। वे आर्थिक प्रगति के हमारे प्रयत्नों में तरह तरह से हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उनके साथ व्यापार और आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए बराबर काम करते रहेंगे। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और यूगोस्लाविया के साथ हमारे सौहार्द और मित्रतापूर्ण संबंध राष्ट्रपति टीटो और अध्यक्ष कोसीगिन की यात्राओं में प्रतिबिम्बित हुए हैं जिनके स्वागत करने की खुशी हाल ही में हमें मिली है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से हमें बहुमूल्य सहायता मिली है जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, और हमें पक्का विश्वास है कि चूंकि हम दोनों शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के हिमायती हैं इसलिए हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते ही जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका हमें काफी मात्रा में बहुमूल्य आर्थिक और अनाज की सहायता बराबर दे रहा है जिससे कि विगत

में हमें अपनी मुश्किलें आसान करने में सहायता मिली है और जिससे भविष्य में हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने जो सद्भावना दिखाई है और जो सहायता दी है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह खुशी की बात है कि अमरीकी महाद्वीप के देशों के साथ हमारी कोई विशेष समस्या नहीं है और उनके साथ हमारे दुतरफा संबंध मित्रता के हैं।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे मित्र देशों ने हमें जो आर्थिक सहायता दी है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध संतोषजनक रीति से विकसित हो रहे हैं और हम उनके साथ अपने संबंधों को विशेषकर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सुदृढ़ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बहुत से देश भारत की मित्रता का सम्मान करते हैं यह उन यात्राओं से प्रकट है कि बहुत से राज्यों के अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा विदेशों के अन्य नेतागण भारत की यात्रा पर आए।

हमें इस बात की खुशी है कि हम दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मेजबान हैं। आशा की जाती है कि यह सम्मेलन इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक खाई को पाटने के लिए कोई ठोस प्रोग्राम देने में सफल होगा। सरकार को इस बात का पक्का विश्वास है कि आज दुनिया के देशों में अमीरी और ग़रीबी का जो अन्तर है वही अस्थिरता और तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ है और यह शांति और सुरक्षा के लिए भी एक ख़तरा है।

घरेलू और विदेशी मामलों का यह विहंगावलोकन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि विधान संबंधी एवं उन अन्य कार्यों का उल्लेख न किया जाए जो कि आपके सामने आएंगे।

आगामी 1968–69 के वर्ष के लिए भारत सरकार की आय-व्यय के अनुमान शीघ्र ही आपके सम्मख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

सरकार चालू अधिवेशन में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद् के सामने लाना चाहती है :—

(1) कम्पनी (संशोधन) बिल, 1968।

(2) सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अवस्थिति बिल, 1968।

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) बिल, 1968।

(4) वायदा संविदा (नियमन) (संशोधन) बिल, 1968।

(5) भारतीय सीमा शुल्क दर की नाम-पद्धति को युक्तियुक्त बनाने से संबद्ध बिल।

(6) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन बिल, 1968।

(7) स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1968।

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बिल, 1968।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 1968 (1968 का पहला) को बलदने के लिए एक बिल रखा जाएगा।

संसद् सदस्यगण, मैं ने कुछ उन महत्वपूर्ण मसलों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है जो हमारे सामने हैं। सदियों बाद भारत के लोग तेज़ी से बदलते हुए दौर से गुज़र रहे हैं। अपने देशवासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं

का जवाब देने की आज हम सबको चुनौती मिली है । महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हित और महत्व के प्रमुख मसलों पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर विचार करने और उनकी सलाह लेने के लिए तैयार रहेगी ।

संसद् सदस्यगण आगामी वर्ष में आपको रचनात्मक परिश्रम करना होगा और इन प्रयासों में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं ।

Members of Parliament,

I am happy to welcome you to this first session of the New Year.

The past year has been challenging and difficult. The country passed through the second successive year of unprecedented drought and scarcity. Considering the disasters that accompanied famines in the past, we can take justifiable pride at the manner in which the entire nation rose to meet the grave threat posed to the very lives of millions of our countrymen. This was possible because of timely and sustained action by the Central and State Governments; the dedicated services rendered by voluntary organizations; the generous and timely support of friendly nations; the hard work and efficiency of our workers in every concerned field; and above all, the unbending spirit and fortitude of the people of the affected areas themselves.

While a year ago the prospects looked bleak and there were dark forebodings about the future, the clouds are now beginning to lift. The production of foodgrain is expected to be better this year than at any time in the past. Preliminary estimates place production at around 95 million tonnes which would be about 20 million tonnes more than in 1965-67 and 6 million tonnes more than the previous record production of 1964-65. With this increase in production, the food situation is expected to be easier. However, a significant portion of this crop will naturally go towards filling empty larders or building up depleted inventories. To bring stability to the food situation, it is essential to build up a sufficiently large buffer stock. It is also necessary to maintain a requisite level of public distribution of foodgrains at controlled rates. Towards these ends, Government are maximising efforts at internal procurement and endeavouring to build buffer stocks of the order of 3 million tonnes. All this requires mobilisation of domestic production. In addition, some imports from abroad will still be necessary.

While favourable weather conditions have contributed to the increase in production, there is no doubt that a substantial breakthrough has been achieved in the field of agricultural production by the use of improved techniques. While in 1966-67 five million acres were sown with high-yielding varieties of seeds. 6 million acres were covered in the last Kharif season alone and a further 9 million acres are expected to be covered in the current Rabi season. Production of commercial crops like cotton, jute, sugarcane, tobacco, groundnuts is also expeted to increase. The minor irrigation programme will cover an additional area of over 3 million acres. There has been an impressive increase in the use of fertilisers; thus the consumption of nitrogenous fartiliser in the current year will be about twice that in 1965-66. The area covered by plant protection measures this year is expected to be about three-quarters more than last year. There have been striking increases in the supplies of tractors, power tillers, pumps, diesel engines and improved implements to farmers. The arrangements for supply of agricultural credit have been strengthened. Progress continues to be made in the implementation of programmes of agricultural education, training, research and extension. The

development programme for agriculture aims at securing national self-sufficiency in foodgrains within the shortest possible time.

The increased agricultural production has resulted in a substantial increase in national income, which is expected to be about 10.8 per cent. higher in the current year than in 1966-67. Improved agricultural performance has also reduced the upward pressure on prices. Over the year as a whole, the increase in wholesale price was 5.7 per cent. as against 16 per cent. during 1966. While the prospects of achieving a reasonable measure of price stability are good, it will be necessary, as I have already said, continue with the system of public distribution of foodgrains and to exercise discipline in respect of fiscal, monetary and income policies.

The severe drought of the last two years adversely affected industrial output because industries based on agriculture could not secure adequate spplies of raw material and there was also a fall in demand due to reduction in incomes. Some capital and producer goods industries faced slackened demand because of restricted investment outlays. The slowing down of industrial expansion has effected employment opportunities particularly for skilled manpower. Selective measures were adopted by Government to stimulate the output of goods both for export and for the domestic market; these included the selective liberalisation of credit, placing of advance orders by public sector undertakings, and avoidance of import of items which could be manufactured indigenously. Improved agricultural production and the consequent rise in national income are expected to stimulate demand for a variety of industrial products during the coming year.

The persistent upward movement of costs and prices, together with the sharp decline in agricultural production during the last two years, adversely affected the competitiveness of our exports. However, with increased production of foodgrains and of agricultural raw materials for industry, the outlook for exports in the coming year is encouraging. In the first seven months of the current financial year, exports were 5.7 per cent higher than in the corresponding period of 1966-67. The engineering industries have secured substantial export orders. As industrial production picks up, it is to be hoped that we shall be able to produce more for overseas markets.

Government continue to help producers and manufacturers to increase and diversify production and develop marketing skills and competence. The endeavour to improve export opportunities for our products and induce importing countries to provide favourable conditions for them has been pressed through multilateral negotiations, bilateral agreements and the day-to-day contacts of our missions abroad. The Agreements reached with the Socialist countries will help to sustain the expansion which has been achieved in our trade with them. The successful completion of the Kennedy round of negotiations will bring to our exporters new opportunities for the export of some of our goods to Market economies. The Tripartite Economic Co-operation Agreement concluded with the U.A.R., and Yugoslavia will help to increase our mutual trade and provide a basis for expanding the area of commercial co-operation with other developing countries. The expansion of exports remains a national objective of the highest priority and will be pursued with vigour.

The adverse balance of trade and the substantial burden of debt servicing, combined with unavoidable imports of foodgrains and raw materials for export production, have continued to make our foreign exchange position difficult over the year. Government have sought the co-operation of friendly countries and international institutions in finding a solution to the debt service problem. A measure-

of assistance to relieve the burden of debt was obtained during the year and further discussions continue. Nevertheless, there was a decline in the foreign exchange reserves and it became necessary to obtain further short-term assistance from the International Monetary Fund.

In any scheme for promoting a more efficient handling of our international trade, the development of our merchant shipping and port facilities occupies a place of crucial importance. In this respect Government have taken a number of important steps, including development of Tuticorin and Mangalore ports, construction of Haldia docks, expansion of the facilities at the existing major ports, reorganisation and modernisation of Hindustan Shipyard and the setting up of a second Shipyard in the public sector at Cochin for the construction of bulk carriers of 66,000 dead weight tons with facilities for repairs to ships up to 85,000 dead weight tons. As for our merchant shipping, the tonnage has now reached a total of approximately two million gross registered tons. Government has set up a Commission to examine comprehensively the problems relating to the finances and economics of major ports, including their modernisation.

No annual survey will be complete without reference to the vitally important programme of Family Planning. This programme made rapid strides during the year. Its acceptability spread to many new sections of rural as well as urban population. Over 2.85 million men and women are estimated to be covered under the various Family Planning programmes. This represents the highest figure reached in any single year so far. However, in order to reach the objective of reducing the annual birth rate from approximately 40 per thousand to 25, an even greater and sustained effort will be required. With this end in view, it is proposed to bring over 6 million additional couples within the ambit of family planning methods and services during the next year. Government have also under consideration certain other measures vitally related to population control.

As one looks to the future, the foremost task which the Government have set themselves lies in imparting a new dynamism to the economy which is recovering from the severe set-backs suffered during the last two years. Government believe that it is only through the process of planning that the difficulties can be overcome and the country can go forward in its social and economic development.

The Planning Commission is engaged in the formulation of the Fourth Five-Year Plan which will now commence from April 1969. Meanwhile, planning for development has been on the basis of Annual Plans. The Annual Plan for 1968-69 will be shortly laid before you. Both the Government and the Planning Commission were naturally anxious that the Plan should be ready in time to be incorporated in the Budget for 1968-69.

The formulation of our Plans calls for an examination of a number of questions. Among these the most important relate to mobilisation of resources, increasing the efficiency and productivity of public sector enterprises and the proper utilization of science and technology. There cannot be adequate mobilisation of internal resources without a much higher rate of domestic savings, both public as well as private. This, in turn, presupposes a regime of self-denial and self-restraint without which we cannot move forward. In order to stimulate effective mobilisation of resources, Government are considering various measures to simplify tax laws, rationalise taxation procedures and streamline the collection machinery.

Government are conscious of the need for urgently raising the efficiency of the public sector. They are

reviewing the organisation and working of this sector in the context of the advice tendered by several expert bodies. Among the aspects under special examination are better management, a more rational and a carefully thought out personnel policy, improved labour relations and effective economies through a more rigorous enforcement of priorities and evaluation.

Members will recall that during the last session of Parliament, the Deputy Prime Minister made a statement on Government's decision to bring general insurance under social control. In the current session, Government propose to introduce a bill to give effect to the decisions contained in that statement.

I referred to the importance which Government's decision to bring general of Science and Technology to our economic development. With this end in view, Government's policy is to bring together, in productive and creative partnership, our scientific research establishments, governmental machinery and industry.

During the year under review, the Thumba Equatorial Rocket Launching Station was formally dedicated. The first Rohini rocket developed at the centre was successfully launched from Thumba. The Experimental Satellite Communication Earth Station at Ahmedabad has been completed and a new station will be set up at Arvi. In the field of nuclear power, the Tarapore Atomic Power Project is expected to be commissioned this year. Two more nuclear power stations are under construction.

Government are conscious of the fact that our administrative structure must not only respond to changing needs but also command the confidence of the people. In order to achieve these purposes, the Administrative Reforms Commission was set up. It has produced a series of reports which have evoked wide interest. It is for the first time that a comprehensive enquiry of this kind has been undertaken in our country. The Commission had addressed itself to the problem of redressing grievances of citizens and had made certain recommendations. Government have now decided to set up a statutory machinery to enquire into complaints alleging corruption or injustice arising out of mal-administration. The machinery will be headed by a Lokpal who will have authority to enquire into the allegations arising out of administrative acts of Central Ministers and Secretaries. The Lokpal will also co-ordinate the working of two other functionaries of the status of Lokayuktas. The first will primarily go into allegations of corruption and the second into other allegations made against Central Government servants lower in rank than Secretaries. A Bill on the subject will be introduced in Parliament during the present session.

There are certain aspects of our national life which are a source of constant concern to Government. Unemployment, specially amongst educated and technically qualified youth, is naturally a matter of disquiet. However, there are no easy, short-term solutions. These problems can only be solved in the measure that our economic growth provides increasing employment opportunities which will absorb the output of our educational and technical institutions as well as take care of population increases. The Planning Commission is critically re-examining the earlier forecast of our manpower requirements. In the meantime, Government earnestly hope that our young men and women, conscious of the dignity of labour, will not hesitate to accept such employment opportunities as might be available at present even if the work involved does not measure up to their technical qualifications.

The socio-economic advancement of the hitherto under-privileged sections

of our society—the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, remains a matter of the utmost interest and concern to Government while a great deal has been done to ameliorate their position Government are conscious that more remains to be done. In this respect, too, the final answer to our problem lies in the speedy growth of our economy.

Both in the short-term and in the longer perspective, all our hopes for economic recovery and further growth depend on orderly functioning of our democratic institutions, the hard work of our people, their sense of self-discipline, the productivity of their labour and the maintenance of industrial peace.

It is a matter of concern that there has been a recrudescence of divisive forces causing conflicts and violence either in the name of region, or language or community. This is a matter for deep national concern transcending party affiliations. It was in recognition of this that both Houses of Parliament had given their unqualified support to efforts being made to curb communalism. The appointment of a Commission of Inquiry headed by a former Judge of the Supreme Court to enquire into the major incidents that took place in different parts of the country in recent time, reflects Government's determination to do everything that lies within its power to curb the forces of disruption.

In a country as large as ours, there will always be problems which agitate people in one part or the other. However, we have a political system in which all these problems can be brought up for dispassionate consideration by the representatives of the people. Reasoned debate and persuasion are the only ways of democratic functioning. Violent agitation in the streets weakens the democratic system and undermines the foundations of national unity.

It is a matter of deep regret to Government that there should be demonstrations and acts of lawlessness over the language issue in certain parts of the country. The overriding objective of Government's language policy is to strengthen the unity of the country and to promote the integration of our people, while providing full opportunity to all sections of the community for self-expression and cultural development. It is Government's earnest hope that all controversies about language will now be ended. Whatever practical problems arise in the implementation of our language policy and programmes should be approached in a spirit of understanding and mutual accommodation.

Government are convinced that co-operation and understanding between the Central and State Governments will continue to serve and advance the larger national interest. On their part, they reaffirm their desire to work in harmony with State Governments irrespective of party affiliations. And, in turn, they expect similar co-operation from State Governments.

Government have made earnest effort to evolve a national consensus on the question of reorganisation of Assam in consultation with leaders of various political parties in Parliament, and the representatives of different sections of opinion in Assam. It is hoped that with their co-operation a satisfactory solution will be found in the near future.

The late Shri Mehr Chand Mahajan, former Chief Justice of India, submitted his report in August last on the question of boundary adjustment between Mysore and Maharashtra and Mysore and Kerala. Government trust that these boundary problems will be satisfactorily resolved.

To meet the persistent threats on our borders, we are continuing to improve the state of preparedness of our Defence Forces; their re-equipment and modernisation are proceeding

steadily. Within the resources available, our air defence arrangements have also been improved as part of the overall Defence Plan. Modernisation of the Navy and expansion of our ship holdings have made good progress. Government will continue the special efforts to promote self-reliance in the field of Defence Production.

The threats across our borders from two of our neighbours continue. While we seek friendly and peaceful relations with them, we are determined to make the necessary sacrifices in defence of the territorial integrity of the country.

The steadfast pursuit of peace, international understanding and co-operation continue to be the basic objectives of our foreign policy. These objectives coincide with our enlightened national interest. Government are convinced that in the present-day world, the principles of co-existence alone provide the framework for international peace.

In the world today, there are many sources of conflict and tension. The most dangerous of these lie in Vietnam and West Asia. Government are convinced that the tragic conflict in Vietnam can only be resolved by political and not by military means. Government have, therefore, consistently, appealed for an unconditional stoppage of the bombing of North Vietnam as the first step towards a peaceful settlement. An increasing number of countries in the world subscribe to this view.

The crisis in West Asia remains unresolved. The longer a just solution is delayed, the more difficult would be the problem. As a member of the Security Council, we have consistently supported all the efforts made to find an early and equitable settlement so that no State is allowed to retain the fruits of aggression and that every State in the area is able to live in peace and security with its neighbours.

Nearer home, we are glad that our relations with Burma, Ceylon, Nepal and Afghanistan are cordial and the areas of mutual understanding and co-operation with them are being steadily enlarged. This growing cordiality has been reflected by the visits of the disinguished leaders of these countries to India, and the visits of the Prime Minister and some of her colleagues to these countries.

It is a matter of regret that our relations with Pakistan and China remain unsatisfactory. We had hoped that the solemn Declaration of Tashkent would provide a basis for the development of peaceful and co-operative relations with Pakistan. Government have earnestly tried to bring about a normalisation of these relations as befits two neighbouring countries with so many ties in common. The restoration of mutual contacts, the full re-establishment of the severed communications and the reactivisation of trade and commerce will facilitate the consideration of other questions. We hope and trust that wisdom and statesmanship will prevail, so that the fabric of friendship and understanding is gradually built up for the benefit of the hundreds of millions of citizens of both countries and in the interest of peace and harmony in the area.

As for our relations with China, we have always wished the Chinese people well. We naturally expect China to respect our right to pursue our own domestic and foreign policies. The principles of mutual respect, non-aggression and non-interference alone provide a durable basis for international relations. On our part, we seek restoration of our relations with China on these principles.

Our country had the honour of being in the vanguard of the movement for the liberation of peoples from colonial rule. We have also stood for the ending of the odious practice of racial discrimination and oppression. We shall continue to espouse the cause of the suppressed peoples of

Southern Rhodesia, South West Africa and of the Portugese colonies for their independence and liberation. To those struggling against the barbarous policy of apartheid, our unrelenting support shall continue.

Our relations with the sovereign and independent States in Africa have become many-sided. We are actively collaborating with a number of these States in economic, technical and educational fields.

It is gratifying to note that the process of detente in Europe continues. Our own relations with the European nations, regardless of their political systems and ideologies, are growing satisfactorily. In different ways, they are partners in our efforts at economic progress for which we thank them. We shall continue to work for the strengthening of our trade and economic relations with them. The continuing cordiality and friendliness of our relations with the U.S.S.R. and Yugoslavia have been reflected in the visits of President Tito and Chairman Kosygin, whom we had the pleasure to receive in our midst recently. We have received valuable assistance from the U.S.S.R. for which we are grateful, and are confident that with our common dedication to the principles of peaceful co-existence our relations will continue to flourish.

Ths U.S.A. continues to extend to us valuable and substantial economic and food aid which has helped us to tide over difficulties in the past and should assist us in the growth of our economy in the future. We are grateful for their understanding and help. With the countries in the American Cotinents, we have happily no special problems and our bilateral relations with them are friendly.

We are thankful to Australia, Britain, Canada, France, Japan, the Federal Republic of Germany and other friendly countries for their economic help.

Our relations with the countries of South and South East Asia are developing satisfactorily and we look forward to further strengthening of our ties with them, more specially in the sphere of economic co-operation.

That the friendship of India is valued by many countries is evident from visits paid to us by distinguished Heads of State and Government and other leaders from various countries.

We are glad to be hosts to the second United Nations Conference on Trade and Development. It is to be hoped that this Conference will succeed in giving to the international community a concrete programme of action designed to bridge the increasing economic gap between developed and developing nations. Government are deeply convinced that the present wide disparities between the rich and poor nations constitute the foremost cause of instability and tension in the world today and pose a threat to peace and security.

This broad survey of our internal and external affairs will not be complete without a reference to the legislative and other business which will come up before you.

The estimates of receipt and expenditure of the Government of India for the next financial year 1968-69 will be presented to you for consideration shortly.

It is the intention of Government to bring before Parliament the following legislative measures during the current session:—

(1) The Companies (Amendment) Bill, 1968.

(2) The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1968.

(3) The Central Silk Board (Amendment) Bill, 1968.

(4) The Forward Contracts (Regulation) (Amendment) Bill, 1968.

(5) Bill to rationalise the nomenclature of the Indian Customs Tariff.

(6) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 1968.

(7) The Gold Control (Amendment) Bill, 1968.

(8) The Central Excises Bill, 1968.

A Bill will be introduced to replace the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1968 (No. 1 of 1968).

Members of Parliament, I have briefly touched upon some of the more important issues before us. After many centuries, the people of India are going through a process of dynamic change. It is a challenge to us all to answer the urges and needs of our people. Important national problems must be placed above party politics. Government will be ready to sit with leaders of all Parties and take counsel with them on major issues of interest and importance to the nation.

May I now commend you to another year of constructive labour and wish you success in your endeavours?

12.4½ hrs.

OBITUARY REFERENCES

MR. SPEAKER: I have to inform the House of the sad demise of five of our friends, namely, Shri Charanjit Rai, Shri Rupnath Brahma, Dr. M. S. Aney, Hafiz Mohammed Ibrahim and Shri Deen Dayal Upadhyaya.

Shri Charanjit Rai was a sitting Member of this House from Dusa constituency of Rajasthan. He used to take an active part in the proceedings of the House and was a forceful speaker. He passed away at Bombay on the 1st January, 1968 at the early age of 50.

Shri Rupnath Brahma was also a sitting Member of this House from constituency of Assam. He was elected to Lok Sabha in the last general election but his seat became vacant as he did not resign his seat in the Assam Legislative Assembly within the prescribed period. He was re-elected to Lok Sabha in the bye-election so caused and took his seat in the House during the last session only. He took active interest in the proceedings of the House particularly those pertaining to Assam. He passed away at Kokrajhar on the 23rd January, 1968 at the age of 66.

Dr. M. S. Aney was a Member of the Central Legislative Assembly, Constituent Assembly of India, Second and Third Lok Sabha during the years 1924—30, 1935—40, 1947-48 and 1959—67. He served the country in various capacities. He was a man of the highest integrity and patriotism. The President recently honoured him with Padma Vibhushan as a mark of the nation's appreciation of his services. In spite of his age and indifferent health, he used to attend the House during the last Lok Sabha and take part in the proceedings of the House with the zeal of a youth. He passed away at Bombay on the 26th January, 1968, at the age of 88.

Shri Hafiz Mohammed Ibrahim passed away at New Delhi on the 24th January 1968, at the age of 78. He had been a Minister in UP for several years and was the Union Minister of Irrigation and Power during the years 1958 to 1963. He was also the Governor of the Punjab for the some time. He was imbued with great qualities of being sober, tolerant a patient in dealing with problems which confronted him.

Shri Deen Dayal Upadhyaya was the President of the Jan Sangh. He met with the tragic and untimely death yesterday, the 11th February

[Mr. Speaker]

1968, near Mughal Sarai. Shri Upadhyaya was a selfless and dedicated worker. The country will be the poorer by his loss.

We deeply mourn the loss of these friends, and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved families.

THE PRIME MINISTER AND LEADER OF THE HOUSE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, we share your sorrow at the passing away of some of our esteemed colleagues in this and earlier Parliaments, and I should like to pay respect to their memory on behalf of this House.

Shri Charanjit Rai had just begun his career as a legislator after having made a mark in the world of sport and in industry.

Shri Rupnath Brahma had rendered great service to Assam, devoting his life to social work and specially to the uplift of the tribal people.

We shall all miss the venerable figure of Dr. M. S. Aney, a figure whom I personally had known since very early childhood. Since the days of Lokmanya Tilak he was in the front rank of national affairs. He was an active Member of the old Central Assembly and of the Constituent Assembly. In the Lok Sabha, his decisive interventions were always heard with respect. I am sure this House will join me in paying a tribute to this great scholar and veteran patriot who served our country well and in many ways.

With your permission, I should also like to refer to Shri Hafiz Mohammed, Ibrahim, an old colleague whom we remember today. He gave dedicated service to the country ever since the old Khilafat days, labouring for unity and integrity of all sections of our society. He was, as you have mentioned, a man of deep humanity, of wisdom and of courtesy. He had varied experience in administration, as a Minister in UP, as a Member of Parliament, as a member of the Union Cabinet and again as a Governor of the Punjab.

Yesterday the death occurred suddenly and in tragic circumstances of Shri Deen Dayal Upadhyaya. As President of the Jan Sangh, he occupied a prominent place in our public life. He was a man of firm ideals to which he dedicated all his energy. His demise will be widely mourned.

On behalf of the House, I should like to offer our condolences and sympathy to the bereaved families.

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr. Speaker, I join with you and the Leader of the House in mourning the deaths of all these friends and national workers.

Shri Charanjit Rai was one of our valued colleagues, in our Party and also in this House. During the short time that he had been a Member of this House, he had evinced great interest in agricultural problems and also in the welfare of the kisans. Though he rose to be a very progressive and prosperous industrialist, he continued to be loyal to his social origin and, therefore, championed the cause of the backward classes, and played his role as one of their leaders in the All-India Backward Classes Organisation.

Dr. Aney was one of our veteran national leaders. I had the honour of being one of his colleagues when he presided over the special session of the Congress in Calcutta, and we both were the recipients of attentions from the police. He had been our colleague for many decades and in the earliest Legislative Assembly when the Congress allowed some of its

members to join here at the Centre, he was one of the tallest people, and from that time onwards he had been in the front rank of our national leaders. As you have yourself said, he was as active as a young member in this House, and even more dutiful towards his responsibilities towards this House than even young people. He was a very great leader of Vidarbha. He wanted to have a separate state for that area, and he made great sacrifices for the people of Maharashtra and Vidarbha. He was one of the valued colleagues and followers of Lokamanya Tilak as well as Mahatma Gandhi.

Shri Deen Dayal Upadhyaya has been one of our friends in our national work during this deade. He was one of the founders of the Jana Sangh which has now risen to be one of our national parties. It was only recently that he became the President of that party after having been its General Secretary for many years. As I looked at him this morning, I did not feel he died of a natural death. The face was there, it looked as if he died in a natural manner. What happened we do not know. What happened while he was going on the train all alone we do not know. We learn now that some enquiry is being instituted. It is proper that an enquiry at the highest level should be instituted lest similar misfortunes should befall people who may be in such eminent position in our national politics, because we must be sure that in our democracy the life, liberty, of every one of our national workers, not to speak of every one of our citizens, is held sacred and would be protected properly and effectively by the Government whether it is at the State level or at the national level. We deeply mourn the death of this young, energetic, powerful personality, and we mourn the death of all our colleagues in our House, and I join you and the Prime Minister in making a request to send our condolences to the bereaved families of these people.

श्री अटल विहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम शोक की छाया में आज यहां एकत्र हैं। लोकनायक बापूजी अणे, जो पुरानी पीढ़ी के प्रकाश-स्तम्भों में से थे, हम से बिछड़ गये। श्री चरणजीत राय, जो लोक सभा में हमारे सहयोगी थे, अकाल में ही काल कवलित हो गये। हाफिज जी को हमने पहले उत्तर प्रदेश में और बाद में दिल्ली में काम करते हुए देखा था। नियति ने उन्हें भी हमारे बीच में से उठा लिया। और आज जो घाव सब से हरा है वह श्री दीनदयाल उपाध्याय के देहावसान का है। वे संसद् के सदस्य नहीं थे, लेकिन भारतीय जनसंघ के जितने सदस्य आज इस सदन में और दूसरे सदन में बैठे हैं, उनकी विजय का, जन संघ को बनाने का, बढ़ाने का, यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वह उपाध्याय जी को है। देखने में सीधे सादे लेकिन मौलिक विचारक, कुशल संगठनकर्ता, दूरदर्शी नेता, सब को साथ लेकर चलने का जो गुण उन्होंने अपने जीवन मे प्रकट किया वह नई पीढ़ी के लिये मार्गदर्शन का काम करेगा। ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने नौकरी नहीं की, वे परिवार के बन्धनों में नहीं बंधे, शरीर का कण कण और जीवन का क्षण-क्षण उन्होंने भारत माता के मस्तक को सौभाग्य के सिंदूर से मंडित करने के लिये समर्पित कर दिया।

जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है व हृदयविदारक हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह किसी रेल दुर्घटना के शिकार हुए। यह तथ्यों के विपरीत है। लखनऊ से पटना जाते हुए मोगलसराय स्टेशन से थोड़ी दूर पर उनका शव पाया गया। अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती तो शरीर लेटी हुई अवस्था में न मिलता, फिर शरीर के ऊपर चादर पड़ी हुई नहीं मिलती, फिर उनके हाथों में 5 रु० का नोट प्राप्त न होता। उनके शरीर पर जो घाव लगे वह भी इस बात की ओर संकेत

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

करते हैं कि मृत्यु रेल दुर्घटना में नहीं हुई। मृत्यु के कुछ और कारण हैं। उन कारणों की छान-बीन होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है। केन्द्रीय सरकार को उच्चस्तरीय जांच करने की आवश्यकता है। 3·45 पर उनकी लाश देखी गई, लेकिन यह प्लेटफार्म पर नहीं लाई गई। क्यों नहीं लाई गई? उनकी जेब में टिकट था। रिजर्वेशन की स्लिप थी। वह लखनऊ से पटना जा रहे थे यह पता लगाया जा सकता था। मगर मोगलसराय स्टेशन के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अगर अचानक हमारा एक कार्यकर्ता वहां न पहुंच जाता तो उनकी लाश लावारिश लाश बना कर अन्तिम संस्कार के लिये भेज दी जाती। प्रश्न केवल एक नेता का ही नहीं है, एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा का भी है, प्रश्न रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का भी है और यह आवश्यक है कि इस मृत्यु पर पड़े हुए सारे रहस्य के पर्दे खोले जायें, तह में जाने का प्रयत्न किया जाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके, जिससे भविष्य में किसी दल को अपना अनमोल कार्यकर्ता न खोना पड़े, जिस से भविष्य में राजनीतिक कारणों की ओर इंगित करने का किसी को अवसर न मिले।

अध्यक्ष महोदय, आपने, प्रधान मंत्री ने और आचार्य रंगा ने जो कुछ कहा है, हम अपने को उसके साथ सम्बद्ध करते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मुझको अन्धेरा दिखाई देता है। मेरे लिये तो रोशनी बुझ गई। वाणी में संयम, दूरदर्शी दृष्टि, सम्पूर्ण देश का विचार, सब को साथ लेकर चलने की भावना, जो भी उपाध्यक्ष जी के सम्पर्क में आये थे वह आज उन के अभाव को अनुभव करेंगे। हमारेलिये उनकी क्षति कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन राष्ट्र के जीवन में फिर ऐसी दुर्घटना न हो, इस के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

13 hrs.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode): Mr. Speaker, Sir, on behalf of the D.M.K. Group, in this House, I wish to join in expressing our deep-felt condolences to those respected leaders of society in their own respective ways, and especially, Charanjit Rai, who was a Member of this House, and who was contributing to the proceedings as well, is no more with us, and the DMK expresses its heart-felt condolences to his bereaved family, and to the families of others also; Mr. Rupnath Brahma, who is no more with us and to Dr. M. S. Aney, who has contributed much in those old days as well as in the third Lok Sabha and who was a great statesman.

We also condole the death of Hafiz Mohammed Ibrahim who was one of those who took part in the liberation movement and who was also one of the greatest statesmen of this country.

I wish to express the deepest condolences on the sad news, in tragic circumstances, of the demise of the President of the Janasangh, Mr. Deendayal Upadhyaya. It is a shocking news to the whole nation; and especially the circumstances under which we hear that he was more or less so helpless; such things should not occur at all in this country and especially for political leaders. The whole nation now feels, whether he belongs to this party or that party, if it was in anyway any attempt by anyone else to murder such a great leader, if it has happened so, such a psychology or such an impression on the mind of the people should be removed from this country once for all.

We express the deepest sympathy of our group and we join with the Chair as well as the Leader of the House in the condolence.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Mr. Speaker, Sir, you will permit me to associate my party and myself with the sentiments of

sorrow which have been expressed at the passing away of so many of our friends and colleagues.

Shri Charanjit Rai who was a Member of this House, to me will continue to be remembered as one of that gallant band of sportsmen who raised high the banner of our country and in the days when India was really supreme in hockey, he was one of those stalwarts who had a distinguished place in the Indian hockey team.

Shri Rupnath Brahma was active mainly in his own State of Assam, but we have known him here also as a Member who was liked and, in particular, his working in Assam, I am sure, will continue to be cherished in this age.

To those of us who had the advantage of coming in touch with the late Dr. Aney, it was a shock to learn that that venerable figure shall no longer be seen not only in the Lok Sabha and its precincts but anywhere else in this country. Dr. Aney was an institution by himself. Those of us who tried to make some study of the history of our national movement are well aware that he has a very secure place in the galaxy of those who contributed substantially to the achievement of our freedom.

When he was in this House, he was already an octagenarian but we found him so active, so regular in his attendance, so constant in his performance of parliamentary duties that he was an exemplar to so many of us who were so many decades his junior. We discovered also the man in him, his affection with nature and the way in which he could make friends with all sorts of people. We noted also his wonderful scholarship and his accomplishment in Sanskrit poetry, but we admired above all a man who was to his finger tips a patriot of the finest order.

Another man built more or less in the same clay was Hafiz Mohammed Ibrahim, whom we saw here for a short while. But we know also that he had played a leading role in our national movement. A nationalist to the marrow, he reminded us of those wonderful days of Hindu-Muslim fraternisation, days which should come back to our minds particularly because of certain dastardly things which are taking place, days of Hindu-Muslim fraternisation which was embedded so to speak in the staunch national character of Hafiz Mohammed Ibrahim. Dr. Aney and Hafiz Mohammed Ibrahim have died full of years and honour. After all, nature will take its toll. Death will come when it will come and we can put in no caveats in regard to that, but in so far as the death of Din Dayal Upadhyaya is concerned, I am afraid the whole country would feel deeply perturbed, particularly because of the circumstances in which his death appears to have occurred. I did not know him too well, but I had occasion to meet him and I could see something of the man, his simplicity and the utter dedication with which he had espoused the cause that he had taken up. He has died in circumstances which are extremely disturbing and I support the plea which has been already put forward by my friends that there should be a through-going investigation into the circumstance in which he met with his death. In his death, we have lost a front rank figure in the political life of the country and it is a thousand pities that our country's condition appears to be that the death of such a man could take place in the conditions which have been reported to us.

I beg of you, Sir, to let us associate ourselves with the condolence that you have expressed and the leader of the House has also supported.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव है और जो भावनायें वक्त की गई हैं उन से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। सब व्यक्तियों को मैं जाती तौर पर तो नहीं जानता था। लेकिन बापू जी अणे को तो मैं विद्यार्थी काल से ही जानता था। मुझे याद है कि जब हम विद्यार्थी थे और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और हम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया तो जिन बड़े बड़े नेताओं ने हम लोगों को प्रेरणा दी उन में से बापू जी अणे भी थे।

बापू जी अणे में और एक बड़ा गुण था जिसको हम महानता कह सकते हैं कि विचारों की भिन्नता होते हुए भी, विरोधी दल में होते हुएभी उनके दिल में हमारे लिए, सब लोगों के लिए जो प्रेम रहा करता था वह कभी कम नहीं हुआ।

1932 में महाराष्ट्र में राजनीतिक परिषद हुई। वहां बापू जी अणे आये थे। यह दिसम्बर महीने में हुई थी। उस वक्त बहुत सारे लोग आये थे। उस वक्त वक्ताओं ने जब मराठी में यह कहा "विद्यार्थ्यांना राजकारणात पड़ने पाहिजे" तब बापू जी अणे ने झट से कहा कि पड़ने की बात नहीं कहनी चाहिये, पड़ने की बात होनी चाहिये। उस समय लोगों को कितनी प्रेरणा मिली, यह मुझे आज भी याद है।

उसके बाद हम ने संयुक्त महाराष्ट्र का आन्दोलन चलाया और आप तो जानते ही हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र के आन्दोलन में बापू जी अणे हमारे एक बंधक थे फिर भी हम जब लोग नौजवानों के नाते उनको मिलने जाया करते थे तो वह हमेशा हम को आशीर्वाद दिया करते थे। एक रोज उन्होंने मुझे कहा, "जोशी खुश रहो"। मैं ने कहा "बापू जी मैं तो तब खुश हूंगा जब वह बात होगी, जो आप नहीं चाहते हैं।" तो उन्होंने कहा, "अगर तुम्हें उस बात से खुशी होगी और वह बात अच्छी है, तो वह हो भी जायेगी।" और वह बात हो गई। इस तरह की उनकी भावना रहा करती थी।

जब उनकी मृत्यु हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा एक मार्गदर्शक चला गया। ऐसे मौके आते थे, जब विरोध और विचारों में भिन्नता होते हुए भी हम उनके पास जा कर उनकी सलाह भी ले सकते थे।

श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु की खबर सिर्फ़ दुखद खबर ही नहीं थी, वह खौफ़नाक भी थी। आदमी को डर पैदा हो, इस तरह की यह घटना है। उसके पीछे जो रहस्य है, वह हमें खोज निकालना चाहिए। उनके साथ मेरा इतना जाती परिचय तो नहीं था, लेकिन मैं दो बार उनसे मिल चुका था। उनकी सरलता और सादगी का परिचय उन को मिलते ही हो जाया करता था। विचारों की भिन्नता तो जरूर थी, मगर इस देश में यदि हम लोग विचारों की भिन्नता नहीं रखेंगे, तो हमारा लोकतंत्र चलेगा भी नहीं। हर एक को चाहिए कि वह अपने विचारों के अनुसार अपने देश की चिन्ता करे। श्री उपाध्याय उन नेताओं में से थे, जो इस तरह अपना काम करते थे। उनकी मृत्यु से उनके दल को तो हानि पहुंची ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने देश और अपने देश के सार्वजनिक जीवन को भी क्षति हुई है।

इस सदन में इस बारे में जो भावनायें और विचार रखे गये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। मैं अपनी तरफ़ से, और अपने दल की तरफ़ से भी, इस बात का समर्थन करता हूं कि इस घटना की एक उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसका रहस्य दुनिया को मालूम होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि और भावनायें व्यक्त करता हूं ।

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Mr. Speaker, Sir, please permit me to associate myself and my group in Parliament with the sentiments of deep sorrow and condolences over the demise of so many of our colleagues either in the House or outside in our public life. Bapuji Aney had played a very important role in the freedom struggle of this country for many years. As a young boy studying in the high school I was naturally amused in the beginning with that 'Maharashtrian Pugree' about whom I used to read very often in the newspapers. Later on, in 1932, when the Congress was made an illegal organisation, when we were conducting the Civil Disobedience Movement, it was decided that we should conduct the annual session in Calcutta. Despite the ban on it by the British Government many of us had gathered secretly from various States as delegates to that Congress session which was held in the Esplanade Maidan. Shrimati late Nalni Sen Gupta was the Chairman of the Reception Committee. We were happy—after all at that time I was just about 23 or 24 years—and when we gathered there we were beaten up like hell by the police and the meeting was dispersed. But in spite of all that it was Shri Aney who encouraged us, who gave us confidence that despite all the ban that the British Government may impose on us the Congress could be held and it was held at that time. Even during that period we were attracted by the simplicity of the man, by the fact that he had the courage of conviction even when he had to differ from his colleagues, and he played a great part in the country's affairs almost till his demise.

Shri Hafiz Mohammed Ibrahim joined the Congress—it is all easy now to join the Congress—when the Congress was not a going concern. In those days of 1935 and 1936, when at any time the Congress Party was likely to be repressed by the British Government, when there was a sort of feeling among the Muslims that they should join the Muslim League, it required a tremendous amount of courage and conviction for him to join the Congress in the national struggle for Independence.

As far as the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya is concerned, I have not had the honour of knowing him personally. But one thing is clear that he was a man who was dedicated to the ideal which he believed to be correct. The circumstances attending his death are extremely suspicious. I support the demand made by Shri Vajpayee that there must be a thorough probe and if anybody is found guilty of this distardly murder, the guilty must be brought to book.

With these words, I once again associate myself with the sentiments expressed by you and I join with you in sending our condolence to the members of the bereaved family.

SHRI NATH PAI (Rajapur): Mr. Speaker, Sir, it is a very sad occasion when the House is called upon to mourn the death of some of our esteemed colleagues. Today is a very sad day when we are here to mourn the death of a large number of Members who belonged to this House and one who never was a Member of this House but was dedicated to the cause of this country.

Sir, I pay my tributes to Shri Charanjit Rai, Shri Rupnath Brahma and Shri Hafiz Mohammed Ibrahim. I should like to say one or two words about Dr. M. S. Aney and Shri Deen Dayal Upadhyaya.

Dr. M. S. Aney belonged to a generation of Indian leaders when scholarship and leadership were not incompatible as they have become today. There was a generation of Indian leadership who thought that *Jnan* and *Karma* will have to go *Vedas*

[Shri P. Ramamurti]

and he, I think, not only preached but in a very rare way combined in his own life *Yoga, Karmasu* and *Kaushalam*. Whatever he undertook, he tried to do it to his very best. He did the job of sitting in this House, attending to his duties as an M.P. or do his duty as a Governor or his more onerous duty as a fighter in the national struggle for Independence but never did this touch of scholarship, its refinement, leave him. It was very inspiring to us. Now and then, when some very presence in the House was inspiring to us. Now and then, when some of us tried to perform and did our very best, nothing was more rewarding than to be patted on the back by Dr. Aney because that came from somebody who was totally disinterested and who took pride in the fact that the new generation was coming up. He was a very rare combination of scholarship, selflessness and dynamic leadership.

One thing that inspired us most was that, though we had to disagree with him on a variety of issues, he brought a rare comibation of deep conviction and total freedom from rancour for what he stood and fought for, that is, the creation of a Vidarbha—I differed and I still differ—and what I always admired was that, though there was r'sk of being misunderstood, he stood for the cause which he thought was a just cause. I do not think we would have like of him in this House.

In the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya, it is not only the Jana Sangh which has suffered a grievous loss but perhaps the country too. He was constantly engaged in one task, in the completion of one revolution. India is simultaneously engaged in many revolutions, social revolution, political revolution and economic revolution. But the one revolution which Tilak, Gandhi and Subhas Chandra Bose tried to push India to nationalism is incomplete. To me, anybody who tries to push it ahead, whatever his Party label may be, is a great son of India. Even today the revolution is incomplete. Before I am misunderstood, let me say, I know how many Chinese there are in the world, how many Pakistanis there are in the world but I do not know how many Indians there are in the world. I know how many Bengalis, Marathis and Tamils there are; I know how many Reddies and Brahmins there are, but I do not know how many Indians there are in this country. Therefore, the completion of this task of making this a nation of Indians is the greatest of our revolutions and Shri Din Dayal Upadhyaya was a constant, valiant fighter on this very vital front of revolution, that of nationalists. He died in very tragic circumstances and, therefore, when we stand by the blow of the news of his death, the shock becomes all the more aggravated when we know of the tragic circumstances. I endorse the plea made by Shri Atal Behari Vajpayee that we shall not be saitsfied if the State Government itself conducts the inquiry; the Union Government should depute some of its best men to associate themselves with this inquiry. I pay my tributes on behalf of my Party to the very baliant and dedicated fighter for India's unity.

SHRI N. C. CHATTERJEE (Burdwan): I want to associate myself with what has been said paying tributes to the memory of those who have departed.

It has been said that Dr. Aney was a great son of Maharashtra, but we are now today paying tributes to his memory as an outstanding fighter in the battle of India's liberation; he was a true votary of India's heritage and culture and he was really dynamic and always inspired confidence. His attendance in the House was an example to many younger men; he used to come here regularly—all of us will remember that—punctually at 11 a.m. and used to stick to his seat to the last minute. That was a wonderful thing. His loss creates a void which cannot be filled. Actually Maharashtra has produced great men.

You must remember that in India today when so many centifugal forces are operating and the regional forces are attempting to cloud our nationalism. Although Dr. Aney fought for Vidharbha, he never forgot India's integrity and he never tried to imperil it. That was the cause which was very dear to him.

I am one of those who were privileged to work with Shri Deen Dayal Upadhyaya and I want to pay a tribute to his sincere work. He organised a big conference at Amritsar. I was associated with an All India organisation and was requested by him to preside over it. I was simply struck by his wonderful organizing effort and his quiet and unostentatious manner of working; he was a synthetic force and he did an admirable work, completely devoid of passions. I had the privilege of being arrested along with Dr. Shyama Prasad Mukerji in the Kashmir movement and I was kept in detention in the Delhi Jail for some days. Dr. Shyama Prasad Mukerji also used to tell me that he had a great admiration for Shri Deen Dayal Upadhyaya; he told me that he was absolutely sincere, straight-forward and devoted to the cause. Whether you agree with his principles or ideologies, you must admire this man and it was mostly due to him that the Jan Sangh is what it is today even after the departure of Dr. Shyama Prasad Mukerji. Jan Sangh is particularly unfortunate in having had a triple tragedy in losing three distinguished Presidents—Dr. Shyama Prasad Mukerji in very tragic circumstances in Srinagar in the Kashmir movement, Dr. Raghvir, and now this young man, when he was at the height of his glory and power. We are all very much perturbed over the manner in which his death was reported and how it happened. I strongly support the suggestion made by Mr. Atal Behari Vajpayee and other friends, specially Mr. Nath Pai, that there should be a thorough and searching probe and those guilty must be brought to book and punished.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय अभी कुछ देर पूर्व आप ने जिन दिवंगत महानुभावों और सदस्यों के नाम पढ़ कर सुनाये हैं उन सब को ही मैं अपनी और अपने सहयोगियों की ओर से समान रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुछ दिन पूर्व आप को स्मरण होगा कि श्री बापू जी अणे जब इसी सदन के सदस्य थे तो इस अवस्था में भी वह कितना जम कर इस संसद में बैठते थे और संसदीय परम्पराओं की कितनी अधिक उनको जानकारी थी ? हम लोग जब कभी कुछ इस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो बापू जी से आ कर के परामर्श करते थे और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। बापू जी अपने जीवन में जिन विचारधाराओं के प्रतीक थे उन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह केवल एक उच्च कोटि के राजनैतिक नेता ही नहीं थे अपितु, वह एक सांस्कृतिक नेता भी थे। जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती थी, संसद के सदस्यों को ज्ञान होगा कि बापू जी श्री लोक नायक अणे अपने बनाये हुए श्लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं लिख कर नव-वर्ष का संदेश देते थे जिस को कि क्षुरादि का संदेश कहते हैं। यह बापू जी का अपना एक स्वरूप था। बापू जी स्वतंत्र भारत के जिस रूप की कल्पना करते थे उसमें स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक भावनाओं के विकास और उसकी सर्वतोमुखी उन्नति की भावना उनके मस्तिष्क में निहित थी।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब इस सदन के वरिष्ठ सदस्य ही नहीं बल्कि एक प्रमुख मंत्री भी रहे। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, कि मैं पांच वर्ष तक उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता रहा हूं जहां के हाफिज साहब निवासी थे। मैंने उन को एक राजनैतिक नेता के रूप में ही नहीं अपितु एक व्यक्ति के रूप में भी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जानने का प्रयत्न किया । हाफिज जी उन हल्की हवाओं से बहुत ऊपर उठे हुए थे जो हिन्दू और मुसलमान के नाम से इस देश में कभी कभी चल पड़ती हैं । उनका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व था और उन्होंने इसी प्रकार की विचारधारा को अपने जीवन में इस देश के समक्ष प्रस्तुत किया ।

सब से बड़े दुःख और सब से घोर चिन्ता की सूचना कल श्री दीन दयाल जी उपाध्याय के आकस्मिक निधन की थी । अभी कुछ दिन पूर्व कालीकट में जब जनसंघ का अधिवेशन हुआ था तो दीन दयाल जी के अपने भाषण और उनके निर्णयों से ऐसा लगता था कि बदलती हुई परिस्थितियों में वह जनसंघ को भी एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे थे । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्ष पद से ले कर और अब तक जनसंघ के जितने भी अध्यक्ष हुए कोई एक व्यक्ति जिस को जनसंघ के महामंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह दीन दयाल जी उपाध्याय ही थे । दूसरे शब्दों में कहें तो मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि श्री दीन दयाल जी उपाध्याय जनसंघ के मस्तिष्क थे । जनसंघ की रीति-नीतियों के निर्माण में उनका एक प्रमुख हाथ था । अब की बार कालीकट अधिवेशन में तो ऐसा लगता था कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों में श्री दीन दयाल जी न केवल जनसंघ को अपितु राष्ट्र को भी एक नयी दिशा देना चाहते थे । जनसंघ के मंच से पहली बार श्री दीन दयाल जी उपाध्याय ने इस देश की एकता को सामने रख कर के यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट बनाने का एक बड़ा क्रान्तिकारी सुझाव दिया था । जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से उपाध्याय जी का देहावसान हुआ है उस से केवल संसद के सदस्य ही नहीं अपितु सारे देश को एक बड़ी चिन्ता व्याप्त हुई है कि राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का निधन अगर इस प्रकार से रहस्यमय ढंग से होने लगा तो इस देश का राजनैतिक जीवन बड़े संकट में पड़ जायगा । मैं अपने मित्र श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के इस कथन के साथ सहमत हूं कि इसकी जांच केवल प्रान्तीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए ताकि देश को इस घटना की वास्तविकता का पता लग सके । इन शब्दों के साथ मैं उन सभी महानुभावों को अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय लोकनायक बापू जी अणे, जो सही अर्थों में लोकनायक थे मेरे ही यवतमाल जिले के रहवासी थे । राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रेरणा हम लोगों को बापू जी से ही मिली थी ।

संसदीय लोकशाही और संविधान के प्रति उन की बड़ी निष्ठा थी । देश के विधायकों के लिए बापू जी अणे एक आदर्श विधायक थे ।

उन्होंने अन्तिम क्षण तक देश की सेवा की और जनसम्पर्क रखा । गये महीने की 2 तारीख को अपने जराजर्जर और गलित गात्र अवस्था में भी उत्कट प्रेम से वह मेरे गांव और घर आये थे और हमारे क्षेत्र को उन्होंने पावन किया था । आयोजित प्रकट सभा में उस वक्त उन्होंने कहा था–

"दुखिते करू दयाम" दुखितों पर दया करो । देश की गरीबी दूर करो । हम लोगों के लिये और देश के लिये वही एक सन्देश उनका अन्तिम सन्देश रहा है । मैं उनके प्रति तथा अन्य दिवंगत मित्र नेताओं के प्रति नम्रतापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

SHRIMATI NIRLEP KAUR (Sangrur): I stand for my party, Shromani Aqali Dal and myself in memory of our veteran public men who served our country in different political spheres and served it well with dignity, honesty and sincerity. Today they are not with us anymore. We mourn

not the demise of their bodies, but the absence of their good deeds. The best homage we can pay them is to remember and follow the good they did.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): You will allow me to associate myself with the sorrow that has been expressed at the demise of these public works and patriots. Allow me also to associate myself with the tribute that has been paid to their memory.

Shri Aney was known to me for more than 50 years. He was the last of the companions of Lokamanya Tilak. He was a great scholar in Sanskrit. He was a man of great hospitality and generosity. We have seen his devotion to duty that even when he was more than 80 he attended this House regularly and sat through the proceedings.

So far as Shri Deen Dayal Upadhyaya is concerned, it is very tragic to contemplate the circumstances in which the death of this young man took place. I came in contact with him sometimes, and I found him as a man simple in his habits, sincere in his outlook. Though he belonged to a party, he had a catholic outlook, and not only the Jana Sangh has lost a great leader, but our country has lost a sincere patriot. I also associate myself with the demand that is made that the circumstances of his death must be investigated not only by the U.P. Government, but also by the Central Government. I have no doubt that this will be done because if this is a case of a political murder, then I do not know how many of us stand in danger. It will be a sad day when an innocent man like Shri Upadhyaya, who offended nobody, should come to an end like this.

I pay my humble tribute to the memory of all these departed patriots.

MR. SPEAKER: May I request the hon. Members to stand in silence for a shortwhile as a mark of respect to the memory of these friends?

The Members then stood in silence for a shortwhile.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

13.36 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 13, 1968/Magha 24, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS II—3067 (Ai) LSD—28-6-68—1010